प्रफुल्ल सुधाकर परब

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 261/2008)

29 जून, 2016

[अभय मनोहर सप्रे और अशोक भूषण, जे. जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1807 - हत्या - प्रकरण के तथ्य, पीड़ित और अभियुक्त एक ही विभाग में काम करनेवाले थे - दुर्भाग्यपूर्ण अभियुक्त पीड़ित के निवास स्थान पर गया और उसे अपने साथ ऑफिस जाने के लिए राजी किया - पीड़ित का पुत्र व पत्नी इसके गवाह थे - एक घंटे बाद अभियुक्त दोबारा पीड़ित के निवास स्थान पर आया और उसे अपने साथ ऑफिस जाने के लिए राजी किया - पीड़ित अपने कार्यालय से लाए गए बेग के साथ कार्यालय गया और वापस नहीं आया - तत्पश्चात पूछताछ करने पर अभियुक्त ने पीड़ित की हत्या करना स्वीकार किया - परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी - विचारण न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया - अपील में निर्धारित किया कि निचले न्यायालय ने पीड़ित की पत्नी के कथनों पर, अभियुक्त की

प्रतिपरीक्षा पर विचार किया और यह सही पाया कि यह वही अभियुक्त है, जो पीड़ित के साथ अंतिम बार साथ देखा गया था - अभियुक्त के पीड़ित के साथ अंतिम बार देखे जाने व मृतक शरीर के खोज के बीच समय का कोई अंतर नहीं था - इस प्रकार अंतिम बार देखने की साक्ष्य सुसंगत हुई - अभिलेख पर आई अन्य साक्ष्यों, शर्ट के बटन, ट्रेजरी बूक, चाबियां तथा अन्य सामान से भरे बेग की बरामदगी घटना की जंजीर को पूर्ण करती है - हेतु को साबित करने की अभियोजन की असफलता प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं डालती - वर्तमान प्रकरण केवल अंतिम बार देखने की थ्योरी पर आधारित नहीं है, अन्य पर्याप्त साक्ष्य घटना की जंजीर को पूर्ण करती थी और अभियुक्त को अपराध से जोड़ती है - इस प्रकार निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय बरकरार रखा गया।

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 वर्तमान प्रकरण में कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य पेश नहीं की गई। अभियुक्त द्वारा पुलिस के सामने अपराध करने की की गई स्वीकृति को वैध स्वीकृति नहीं कहा जा सकता जैसा कि सेशन न्यायालय द्वारा सही माना गया। अभियोजन मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। [पैरा 8] [102-F]

1.2 किसी प्रकरण में जहां 07.12.1996 पर अंतिम बार साथ देखे जाने की साक्ष्य के आधार पर निचली अदालतों द्वारा विश्वास किया गया है। गवाह पी.ड. 8 ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह अपने पति के साथ अपने भाई को फोन करने के लिए टेलीफोन बूथ पर गई थी और जब वह अपने भाई से बात कर रही थी, तभी वहां आरोपी फिर से आया और पीड़ित से बातचीत की। तत्पश्चात अभियुक्त व पीड़ित दोनों घर पर आए। पीड़ित ने अपना बेग जो अपने ऑफिस से लाया था, उठाया और अभियुक्त के साथ उसी दिन 9.15 पी.एम. पर ऑफिस गया। बाल गवाह पी.ड. 11 पर भी सेशन न्यायाधीश ने विश्वास किया, जिसने आरोपी के साथ पीड़ित द्वारा घर छोड़ने के बारे में वही बयान दिए थे। उच्च न्यायालय ने घटना के समय बाल गवाह की उम्र को देखते हुए उस गवाह पर भरोसा नहीं करने का फैसला लिया। [पैरा 12] [105-C-F]

1.3 निचले दोनों न्यायालयों ने पीड़ित की पत्नी पी.ड. 8, अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा पर विचार करते हुए यह सही पाया कि वह अभियुक्त ही था, जिसे अंतिम बार पीड़ित के साथ 07.12.1998 को देखा गया था। अंतिम बार देखने की थ्योरी एक ऐसी परिस्थिति है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन यह अच्छी तरह तय है कि केवल अंतिम बार देखने की थ्योरी के आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साथ ही यदि अंतिम बार देखे जाने और घटना की तारीख के बीच लंबा समय अंतराल है तो

अंतिम बार देखे जाने की साक्ष्य समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रकरण में जहां लंबा समय अंतराल नहीं है, पीड़ित अभियुक्त के साथ दिनांक 07.12.1998 को रात्रि को 9 बजे के बाद गया था और अगले दिन सुबह पीड़ित की पत्नी ने काफी तलाश की, अभियुक्त से मुलाकात की और उसे पुलिस स्टेशन ले गई। दिनांक 09.12.1996 को सुबह अभियुक्त अपने अपराध की संस्वीकृति करता है तत्पश्चात शव और अन्य सामान घटनास्थल से बरामद किए जाते हैं, इस प्रकार अभियुक्त के अंतिम बार देखे जाने व शव की बरामदगी के बीच कोई समय अंतराल नहीं था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि हत्या 09.12.1996 को हुई थी। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में कोई समय अंतराल नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतिम बार देखे जाने की साक्ष्य महत्वपूर्ण और सुसंगत हो जाती है। निचले न्यायालय द्वारा इस पर सही विश्वास किया गया है। अभिलेख पर अन्य साक्ष्य घटना की जंजीर को पूर्ण करती है। घटनास्थल से शर्ट के तीन बटन व पत्थर की बरामदगी, खजाने की किताबांे वाले थैले की बरामदगी, चाबियों व अन्य वस्तुओं की बरामदगी जो पीड़ित द्वारा ऑफिस जाते समय साथ ले जाई गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा उस पंचनामे पर विस्तृत रूप से विचार किया, जो कि मौके पर तैयार किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा सही निरीक्षण किया गया कि पंचनामा एक समग्र दस्तावेज है, जिसमें अभियुक्त द्वारा किए गए कथन से संबंधित कुछ विवरण शामिल है और इसमें वैसे विवरण भी हैं जिससे घटना के दृश्य का पंचनामा कहा जा सकता है। स्वतंत्र गवाह पी.ड. 9

घटनास्थल, शव व अन्य वस्तुओं की बरामदगी का स्वतंत्र गवाह था, जिससे बचाव पक्ष द्वारा पूर्ण रूप से जिरह की गई थी। अभियुक्त का वह आचरण जो साक्ष्य द्वारा न्यायालय के समक्ष आया, घटना के समय उसके द्वारा पहने हुए कपड़ों की बरामदगी, चाबियों की बरामदगी जो मृतक के पास उसके घर से निकलते समय उसके पास थीं, घटनाओं की श्रृंखलाओं को पूर्ण करती है और बिना किसी संदेह के पता चलता है कि वह आरोपी ही था, जिसने अपराध को अंजाम दिया है। [पैरा 15] [106-H; 107-A-F; 108-C-E]

1.4 अपराध करने का हेतु एक ऐसी चीज है जो अभियुक्त के दिमाग में छिपा होता है और यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह अभियोजन पक्ष के लिए मामला साबित करना असंभव कार्य है कि हत्यारे को किसी विशेष व्यक्ति को मारने के लिए क्या हेतु था। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के हेतु पर विचार करते हुए कहा कि हालांकि अभियोजन पक्ष हेतु के बारे में ज्यादा निश्चित नहीं है, पी.ड. 4 व पी.ड. 6 की साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त के झूठ बोलने के इरादे के बारे में एक क्षीण संभावना पैदा हो जाती है। प्रारंभिक कहानी के विपरीत अभियुक्त पीड़ित के खिलाफ क्रोधित था क्योंकि पीड़ित ने उसे बार गर्ल के साथ शादी करने के मुद्दे पर उसे परेशान किया करता था। हेतु एक मानसिक स्थिति है, जो हमेशा अभियुक्त के मस्तिष्क के आंतरिक हिस्से में

बंद रहती है और हेतु को स्थापित करने में अभियोजन की असफलता आवश्यक रूप से अभियोजन की पूरी कहानी की विफलता का कारण नहीं बनती। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उक्त दृष्टिकोण का समर्थन किया जाता है। [पैरा 16, 18] [108-G; 109-G-H; 110-A]

1.6 न्यायमित्र ने कहा कि पी गवाह के रूप में परीक्षित नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने पीड़ित को बतया कि उसे पी ने कार्यालय में बुलाया था। जब पी.ड. 1 जो पी.टी.एस. में टेलीफोन संचालक था, की साक्ष्य से अभिलेख पर यह आया कि दिनांक 07.12.1996 की रात को पीड़ित का कोई संदेश नहीं था। अभियोजन द्वारा इनको पेश करने का कोई परिणाम नहीं है। [पैरा 19] [110-B-C]

1.7 यह प्रस्तुत किया गया कि पी.ड. 8 ने अपने बयानों में कहा था कि दिनांक 07.12.1996 पर पीड़ित ने 9 पी.एम. डीनर लेने के बाद घर छोड़ दिया, लेकिन पीड़ित के पेट में कोई भोजन नहीं पाया गया जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट दर्शाती है। रिपोर्ट में उच्च न्यायालय ने विचार किया कि पोस्टमॉर्टम टिप्पणियों का हिस्सा यह दर्शाता है कि पीड़ित का पेट खाली था, इसलिए कल्पना की इस साक्ष्य को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो पीड़ित के अभियुक्त के साथ जाने के ज्ञान का दावा करती है। इस प्रकार यह माना जाता है कि के की यह साक्ष्य की मृतक अभियुक्त के साथ गया था और अभियोजन पक्ष विश्वसनीय साक्ष्य के साथ परिस्थितियों को

स्थापित किया है और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का समर्थन किया जाता है और वर्तमान मामला अंतिम बार देखने की थ्योरी का नहीं है बल्कि घटना की जंजीर को पूर्ण रूप से जोड़ने तथा अभियुक्त को अपराध से जोड़ने हेतु पर्याप्त साक्ष्य दी गई है। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्यों पर विस्तृत रूप से विचार कर अभियुक्त द्वारा दायर की गई अपील को सही खारिज किया है। [पैरा 20, 21] [110-D-H]

गंभीर बनाम महाराष्ट्र राज्य 1982 (2) एस.सी.सी. 351; के. वी. चाको बनाम केरल राज्य 2001 (9) एस.सी.सी. 277; तिरमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 (10) एस.सी.सी. 681: 2006 (7) पूरक एस.सी.आर. 156; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश 2005 (3) एस.सी.सी. 114: 2005 (2) एस.सी.आर. 1132; दीपक चंद्रकांत पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 (10) एस.सी.सी. 151; रविंदर कुमार व अन्य बनाम पंजाब राज्य 2001 (7) एस.सी.सी. 690: 2001 (2) पूरक. एस.सी.आर. 463; परमजीतसिंह बनाम उत्तराखंड राज्य 2010 (10) एस.सी.सी. 439: 2010 (11) एस.सी.आर. 1064 संदर्भित -

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

1982 (2) एस.सी.सी. 351	संदर्भित किया गया है	पैरा 8
2001 (9) एस.सी.सी. 277	संदर्भित किया गया है	पैरा 8

2006 (7) पूरक एस.सी.आर.156	संदर्भित किया गया है	पैरा 9
2005 (2) एस.सी.आर. 1132	संदर्भित किया गया है	पैरा 10
2006 (10) एस.सी.सी. 151	संदर्भित किया गया है	पैरा 14
2001 (2) पूरक एस.सी.आर. 463	संदर्भित किया गया है	पैरा 16
2010 (11) एस.सी.आर. 1064	संदर्भित किया गया है	पैरा 17

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं. 261/2008

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 703/ 2001 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 14.02.2006 से।

डॉ. सुशील बलवाड़ा, श्रीलोक नाथ आर., अपीलार्थी के अधिवक्तागण।

निशान्त रमाकान्तराव कटनेश्वरकर, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता।

न्यायायलय का निर्णय न्यायधीश अशोक भूषण, जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. अपीलकर्ता ने यह अपील वर्ष 2001 की आपराधिक अपील संख्या 703 में न्यायिक उच्च न्यायालय, बॉम्बे के दिनांक 14.2.2006 के फैसले के खिलाफ दायर की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और ग्रेटर बॉम्बे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के खिलाफ दर्ज वर्ष 1997 के सत्र मामला संख्या

459 में दिनांक 31.07.2001 को पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि की है जो कि अभियुक्त के विरूद्ध आजीवन कारावास और 5000/- रुपये का जुर्माना के दण्डादेश के रूप में पारित किया गया था।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि पीड़ित प्रभुदास नारायण राउत और अभियुक्त प्रफुल्ल सुधाकर परब दोनों महाराष्ट्र राज्य के पुलिस विभाग में कार्यरत थे। पीड़ित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मरोल में वरिष्ठ क्लर्क के रूप में कार्यरत था, जबकि अभियुक्त एलए-IV, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, मरोल से जुड़े पे शीट क्लर्क के रूप में कार्यरत था। दिनांक 7.12.1996 को, पीड़ित अपना कार्यालय का काम शाम 6:30 बजे समाप्त करने के बाद 7:30 बजे अपने आवास पर पहुंचा। अभियुक्त लगभग 8:00 बजे पीड़ित के आवास पर आया और पीड़ित को बताया कि उसके वरिष्ठ श्री पाटिल ने उसे कार्यालय बुलाया है और पीड़ित को उसके साथ कार्यालय जाना चाहिए। पीड़ित ने पीटीएस मरोल को फोन करने के बाद कहा कि उसे कार्यालय नहीं बुलाया गया है और वह अभियुक्त के साथ नहीं जाएगा। जब अभियुक्त पीड़ित के घर आया तो पीड़ित की पत्नी कल्पना राउत और उसका बेटा अनीस भी मौजूद थे। पीड़ित ने अपनी पत्नी से यह भी कहा कि वह सोमवार को पूछताछ करेगा कि यह झूठा संदेश किसने दिया। रात लगभग 9 बजे, पीड़ित और कल्पना पास के टेलीफोन बूथ पर गए और जब कल्पना अपने भाई के साथ बातचीत कर रही थी, तब अभियुक्त बच्चे

अनीस से दंपति के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के बाद फिर से टेलीफोन बूथ पर उनके पास आए। अभियुक्त ने प्रभुदास को अपने साथ ऑफिस चलने के लिए मना लिया। टेलीफोनिक कॉल खत्म होने के बाद कल्पना पीड़ित और अभियुक्त के साथ पीड़ित के घर लौट आई। पीड़ित ने कार्यालय से लाए गए बैग को उसकी सारी सामग्री के साथ उठाया और रात 9:00 बजे के बाद अभियुक्त के साथ घर से निकल गया। 7.12.1996 को रात 9 बजे के बाद घर से निकलने के बाद प्रभुदास कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह पत्नी कल्पना ने टेलीफोन ऑपरेटर पीटीएस, मरोल से अपने पति के बारे में पूछताछ की। उसे सूचित किया गया कि पिछली रात को कोई भी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, मरोल के कार्यालय नहीं गया था। कल्पना ने एक रिश्तेदार के साथ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, मरोल गई और पूछताछ की। पुलिस कांस्टेबल सनप और खामकर, जो मृतक के सहकर्मी थे, ने कल्पना को सुझाव दिया कि वह उस व्यक्ति का पता लगाए जिसके साथ उसका पति कल रात गया था। कल्पना ने सावंत से संपर्क किया जो पीड़ित का मामा था। सावंत कल्पना को अपनी बहन यानी अभियुक्त की मां के पास ले गया, अभियुक्त वहां मौजूद नहीं था। कल्पना को उसकी मां ने अभियुक्त की तस्वीर सौंपी, जिस तस्वीर से कल्पना ने अभियुक्त की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की, जिसके साथ उसका पति कल रात गया था। इसके बाद उसी दिन सावंत परिवार ने सूचित किया कि अभियुक्त उनके आवास पर मौजूद है। कल्पना सावंत परिवार के पास गईं और

अभियुक्त से अपने पति के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। अभियुक्त ने गोलमोल जवाब दिया। अभियुक्त ने साफ इंकार कर दिया कि वह पिछली रात को राऊत के घर गया था। अभियुक्त को कल्पना राऊत और उसके परिजन पुलिस स्टेशन मेघवाडी ले गये। कल्पना की मुलाकात पुलिस सब इंस्पेक्टर शिंदे से हुई जिन्होंने कल्पना राऊत का बयान दर्ज किया और प्रभुदास राऊत के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई। अभियुक्त को पुलिस स्टेशन में ही रुकने के लिए कहा गया। शिंदे ने अभियुक्त से पीड़िता के ठिकाने के बारे में पूछताछ की, अभियुक्त जवाब देने में आनाकानी कर रहा था। शिंदे और इंस्पेक्टर सोनार द्वारा आगे पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वह प्रभुदास राउत को अपने दो अन्य दोस्तों दलवी और वैनगंकर के साथ पनवेल के एक होटल में ले गया था। पुलिस टीम अभियुक्त को पनवेल ले गई, जहां एक सुमन मोटल के बारे में पता चला। होटल के कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि प्रभुदास और अन्य दोनों होटल में नहीं आए थे और न ही वहां रुके थे। अभियोजन पक्ष का मामला आगे यह है कि 9.12.1996 की सुबह अभियुक्त से अग्रिम पूछताछ करने पर, अभियुक्त ने प्रभुदास राउत की हत्या की बात स्वीकार की और जिस स्थान पर उसने हत्या की थी उसे दिखाने और शव दिखाने की इच्छा प्रकट की। अभियुक्त द्वारा पुलिस दल को घटनास्थल पर ले जाया गया जहां सर्च लाइट में शव को एक बड़े पानी के पाइप के अंदर धकेला हुआ देखा गया। पुलिस दल ने दो कांस्टेबलों को उस स्थान की सुरक्षा में

लगाकर सूरज की रोशनी में पंचनामा करने का निर्णय लिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके बाद सुबह 8:00 बजे फिर से पुलिस दल अभियुक्त के साथ दो पंचों की उपस्थिति में घटनास्थल पर गया, एक पंचनामा Exh.-24 तैयार किया गया, कुछ सामान जिसमें मृतक के शव के पास से एक बड़ा पत्थर, शर्ट के नीले रंग के तीन बटन और एक रेक्सीन बैग बरामद किया गया। शरीर पर चोट के निशान थे। मृतक का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और सिर पर चोट के निशान थे।

3. अभियुक्त ने आगे उन कपड़ों को दिखाने की इच्छा व्यक्त की जो उसने घटना के समय पहने हुए थे। अभियुक्त पुलिस पार्टी को अपने माता-पिता के घर ले गया जहां से अभियुक्त द्वारा पहने गए कपड़े बरामद किए गए। गवाह की उपस्थिति में पंचनामा Exh..-35 तैयार किया गया। इसके बाद, अभियुक्त पुलिस पार्टी को पीटीएस, मरोल ले गया जहां उसने मृतक की जेब से निकाली गई चाबियों का गुच्छा रखा हुआ था। पंच के साथ पुलिस दल पीटीएस, मरोल गया जहां राइफल रखने के लिए स्टैंड के नीचे गार्डरूम में चाबियों का गुच्छा वाला एक बैग मिला और मेमो Exh..-30 और पंचनामा Exh..-30ए तैयार किया गया।

4. अभियुक्त पर मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों का परीक्षण किया और विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया

गया। बचाव पक्ष ने बचाव मामले के समर्थन में किसी भी गवाह का परीक्षण नहीं किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया, यह मानते हुए कि घटनास्थल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और न ही अभियुक्त के इकबालिया बयान को संस्वीकृति माना जा सकता है। हालाँकि, सत्र न्यायाधीश ने पीडब्लू-8 कल्पना राऊत और पीड़ित के बेटे पीडब्लू-11 अनीश राऊत के साक्ष्य पर विश्वास किया कि यह अभियुक्त था जिसे आखिरी बार पीड़ित के साथ देखा गया था और जिसके साथ पीड़ित 7.12.1996 को रात 9 बजे के बाद बाहर गया था। घटनाओं की श्रृंखला यह स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यह अभियुक्त था जिसने हत्या की थी। धारा 364 के तहत अपराध के संबंध में, सत्र न्यायाधीश द्वारा यह माना गया कि उक्त आरोप कायम नहीं होता है। सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की और अपील खारिज कर दी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-8 के बयान पर भरोसा करते हुए कहा कि यह अभियुक्त था जिसे आखिरी बार पीड़ित के साथ देखा गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष को बाल गवाह यानी पीडब्लू-11 पर आधारित नहीं करने का निर्णय लिया। कल्पना के साक्ष्य को विस्तृत रूप से नोट किया गया था और घटनाओं के क्रम और घटनाओं की श्रृंखला को अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्यों से समर्थन मिला, जिसमें पीडब्लू-15 शांता राम सावंत और स्वतंत्र गवाहों के साक्ष्य के साथ-साथ इंस्पेक्टर

सोनार और सब इंस्पेक्टर शिंदे के बयान भी शामिल थे। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अभियुक्त की सजा की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी।

5. यह अपील अपीलकर्ता (इसके बाद 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित) द्वारा न्याय मित्र के माध्यम से दायर की गई है। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान न्याय मित्र ने अपील के समर्थन में निम्नलिखित दलीलें पेश कीं:

(i) घटनाओं का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। परिस्थितिजन्य संबंध संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

(ii) पीडब्लू-8 कल्पना राउत ने गवाही दी कि उनके पति ने 7.12.1996 को रात का खाना खाया और रात के खाने के बाद अभियुक्त के साथ चले गए। भोजन का पेट में पाया जाना जरूरी था जिसे मेडिकल रिपोर्ट में खंडित कर दिया गया है।

(iii) अभियोजन पक्ष की कहानी यह थी कि अभियुक्त मृतक को बुलाने के लिए दो बार मृतक के पास गया कि पाटिल साहब उसे बुला रहे हैं। हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा पाटिल साहब का परीक्षण नहीं किया गया।

(iv) पुलिस जांच में अभियुक्त पर यह आरोप नहीं लगाया गया कि उसका मृतक के साथ कोई द्वेष, प्रतिद्वंद्विता या खराब संबंध था। हत्या का कोई हेतु साबित नहीं किया जा सका, इसलिए दोषसिद्धि गलत है।

(v) चाबियों की बरामदगी इस बात का समर्थन करती है कि अभियुक्त पुलिस खजाने में चोरी की योजना बना रहा था, जहां नकदी रखी गई थी, लेकिन पूरे अभियोजन साक्ष्य में, यह अभिलेख पर नहीं लाया गया कि वहां कितनी नकदी थी।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने फैसले का समर्थन किया है। यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालतों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष और निणर्य ठोस सबूतों पर आधारित थे और अभियोजन पक्ष द्वारा लाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थे। अपील में कोई आधार नहीं है।

7. हमने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

8. वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें कोई चश्मदीद गवाह पेश नहीं किया गया। 9.12.1996 की सुबह अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान जिसमें अभियुक्त द्वारा हत्या कबूल करने की बात कही गई है, को वैध संस्वीकृति नहीं कहा जा सकता है जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने

सही ठहराया है। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किया है। क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है और क्या दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत थे, ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर इस अपील में दिया जाना है। इस न्यायालय ने कई अवसरों पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के संबंध में विधि पर विचार किया है। गंभीर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1982 (2) एससीसी 351 में शीर्ष न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान किया जाना है, उन्हें सुसंगत और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। गंभीर बनाम महाराष्ट्र राज्य (सुप्रा) के उपरोक्त फैसले का हवाला देते हुए, सिद्धांतों को केवी चाको बनाम केरल राज्य, 2001 (9) एससीसी 277 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर से दोहराया गया था, जिसमें पैराग्राफ 5 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

> "5. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि के संबंध में विधि अच्छी तरह से स्थापित है। जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को तीन परीक्षणों को पूरा करना चाहिए: (1) जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाना

चाहिए, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए (2) वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करना; (3) परिस्थितियों को, संचयी रूप से लेते हुए, इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी और ने नहीं। दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषिता से असंगत होने चाहिए।"

9. त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 (10) एससीसी 681 में, पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

"12. मौजूदा मामले में घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में सामान्य सिद्धांत यह है कि जिन परिस्थितियों से

अपराध का अनुमान लगाया जा रहा है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए; वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों; संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और उन्हें अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए। और उसकी निर्दोषिता से असंगत है।"

10. यूपी राज्य बनाम सतीश, 2005 (3) एससीसी 114 में इस न्यायालय ने दोहराया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित विधि की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। पैराग्राफ 14,15 और 16 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

"14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसे 1952 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित विधि की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

15. हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम एमपी राज्य, एआईआर (1952) एससी 343 में यह इस प्रकार देखा गया था;

"यह अच्छी तरह से याद रखना है कि ऐसे मामले में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाना है, उन्हें पहले पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए। फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए जो साबित होने के लिए प्रस्तावित परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक परिकल्पना को बाहर कर दें। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो यहां तक पूर्ण है कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ते हैं और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दर्शाता हो कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

16. शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर (1994) एससी 1622 में बाद के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। इसमें, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटने के

दौरान, यह माना गया है कि यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था कि श्रृंखला पूर्ण है और अभियोजन पक्ष की खामियों को झूठे बचाव या दलील से ठीक नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के शब्दों में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि से पहले जिन शर्तों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, वे हैं:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या करने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए; और (5) सबूतों की एक श्रृंखला इतनी संपूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दिखाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

11. वर्तमान मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की जांच ऊपर बताई गई विधि के आलोक में की जानी चाहिए।

12. वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां 7.12.1996 को आखिरी बार साथ देखे जाने की साक्ष्य पर नीचे के न्यायालयों द्वारा भरोसा किया गया है। मृतक अपने कार्यालय में उपस्थित हुआ और शाम 6:30 बजे एक अन्य कांस्टेबल पीडब्लू-2 दिलीप आत्माराम वैनगंकर के साथ चला गया, जो भी 7.12.1996 को ड्यूटी पर था, जिसने कहा कि वह पीड़ित के साथ शाम 6:30 बजे कार्यालय से निकला और उसने पीड़ित को शाम 7:30 बजे जोगेश्वरी छोड़ दिया। मृतक की पत्नी पीडब्लू-8 कल्पना राऊत ने अपने बयानों में कहा है कि अभियुक्त 7.12.1996 को रात 8:00 बजे आया और पीड़ित को अपने साथ कार्यालय चलने के लिए कहा क्योंकि उसे पाटिल साहब ने बुलाया था। पीड़ित ने पीटीएस, मरोल को फोन किया और

टेलीफोन ऑपरेटर ने उसे सूचित किया कि उसके लिए कोई संदेश नहीं था, जो साक्ष्य में भी सामने आया है। पीडब्लू-8 कल्पना राउत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने पति के साथ अपने भाई को काॅल करने के लिए अपने घर के पास टेलीफोन बूथ पर गई थी और जब वह अपने भाई से बात कर रही थी, तो अभियुक्त फिर से आया और पीड़ित के साथ बातचीत की। इसके बाद पीड़ित और अभियुक्त दोनों घर पर आ गए। पीड़ित ने अपना बैग उठाया जो वह ऑफिस से लाया था और उसी दिन रात करीब 9:15 बजे अभियुक्त के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने बाल गवाह पीडब्लू-11 अनीश पर भी भरोसा किया, जिसने पीड़ित द्वारा अभियुक्त के साथ घर छोड़ने के बारे में भी यही बयान दिया था। उच्च न्यायालय ने घटना के समय बच्चे की उम्र को देखते हुए बाल गवाह पर भरोसा नहीं करने का निर्णय लिया।

13. अंतिम बार देखे गए सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है, यह इस न्यायालय के समक्ष बार-बार विचार के लिए आया है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश (सुप्रा) में इस बात के सकारात्मक सबूत थे कि गवाहों ने मृतक और अभियुक्त को एक साथ देखा था। इस न्यायालय द्वारा पैरा 22 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

> "आखिरी बार देखा गया सिद्धांत चलन में आता है जहां उस समय जब अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार जीवित

देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया था के बीच का समय-अंतराल इतना कम है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के रचयिता होने की संभावना असंभव हो जाती है। कुछ मामलों में यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना मुश्किल होता है कि मृतक को आखिरी बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, जब कि लंबा अंतराल मौजूद हो और इस बीच में अन्य व्यक्तियों के आने की संभावना मौजूद हो। अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखे जाने के किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, उन मामलों में अपराध के निष्कर्ष पर आना खतरनाक होगा। इस मामले में सकारात्मक सबूत हैं कि मृतक और अभियुक्त को पीडब्लू-2 के साक्ष्य के अतिरिक्त गवाहों पीडब्ल्यू 3 और 5 द्वारा एक साथ देखा गया था।"

14. दीपक चंद्रकांत पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2006 (10) एससीसी 151 में, मृतक की पत्नी और बेटे के इस आशय के बयान कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ता की कंपनी में देखा गया था, को इस आधार पर चुनौती देने की मांग की गई थी कि मृतक पर हमला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। उक्त दलील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि

अभिलेख पर मौजूद अन्य सबूतों के साथ अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति पर अपराध सिद्ध पाया गया है। पैरा 14 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

> "अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारे सामने यह भी प्रस्तुत किया कि पीडब्लू 15 और 13 के इस आशय के साक्ष्य कि अपीलकर्ता को आखिरी बार अपीलकर्ता की कंपनी में देखा गया था, इस तथ्य के मद्देनजर अप्रासंगिक हो गया कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि मृतक पर हमला अभियुक्त द्वारा किया गया था। हमारे विचार में, प्रस्तुतीकरण से अपीलकर्ता को कोई मदद नहीं मिलती। इस मामले में, यह परिस्थिति कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ता की कंपनी में पीडब्लू 15 और 13 द्वारा देखा गया था, एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों के साथ विचार करने पर अभियुक्त का अपराध साबित हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने उस मामले से इतर कोई मामला स्थापित करने का प्रयास किया हो जो कि उन प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना था जो कि पक्षद्रोही हो गए। चूंकि प्रत्यक्षदर्शी गवाह पक्षद्रोही हो गए,

इसलिए यह परिस्थिति कि अपीलकर्ता मृतक के साथ गया था और आखिरी बार उसने उसे देखा था, उसके अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में एक परिस्थिति के रूप में माना गया।"

15. दोनों निचली अदालतों ने पीड़ित की पत्नी पीडब्लू-8 कल्पना राऊत के बयानों पर विचार किया है, जिसमें अभियुक्त के विद्वान वकील द्वारा की गई जिरह का हवाला दिया गया है और सही पाया है कि यह अभियुक्त था जिसे 7.12.1996 को पीड़ित के साथ आखिरी बार देखा गया था और यह अभियुक्त था, जो पीड़ित के घर आया और पीड़ित को यह कहकर अपने साथ ले गया कि पीड़ित को उसके वरिष्ठ द्वारा कार्यालय में बुलाया गया है। आखिरी बार देखे जाने का सिद्धांत एक परिस्थिति है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है कि केवल आखिरी बार साथ देखे जाने के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। इसके अलावा, यदि आखिरी बार एक साथ देखे जाने और घटना की तारीख के बीच लंबा समय अंतर हो, तो आखिरी बार एक साथ देखे जाने के साक्ष्य का महत्व बहुत कम हो जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा मामला है जहां कोई लंबा समय अंतराल नहीं है। पीड़ित दिनांक 7.12.1996 को रात 9 बजे के बाद अभियुक्त के साथ चला गया और अगले दिन सुबह पत्नी ने कड़ी तलाश की, अभियुक्त से मिली और उसे पुलिस स्टेशन ले गई।

8.12.1996 की सुबह से पत्नी द्वारा यह बयान देते हुए तलाशी ली गई कि यह अभियुक्त था जो पीड़ित के घर आया और पीड़ित को यह कहकर ले गया कि उसे कार्यालय में उसके वरिष्ठ द्वारा बुलाया जा रहा है। 8.12.1996 की शाम, पीडब्लू-8 कल्पना राउत अपने रिश्तेदारों की मदद से अभियुक्त को पुलिस स्टेशन ले जा सकीं और अभियुक्त पुलिस स्टेशन में ही रहा और पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई। 9.12.1996 की सुबह अभियुक्त द्वारा अपना अपराध कबूल कर लिया जाना बताया गया है और उसके बाद घटनास्थल से शव और अन्य सामान बरामद किए गए थे। इस प्रकार, अभियुक्त को आखिरी बार एक साथ देखे जाने और शव मिलने के बीच कोई समय अंतर नहीं है। अभियोजन का मामला यह है कि हत्या 9.12.1996 को ही हुई थी। इस प्रकार, वर्तमान बिल्कुल भी समय अंतराल का मामला नहीं है, इसलिए, आखिरी बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है और नीचे के न्यायालयों द्वारा इस पर सही ढंग से भरोसा किया गया है। अभिलेख पर अन्य साक्ष्य भी हैं जो घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करते हैं। घटनास्थल से शर्ट के तीन बटन बरामद; उस बैग की बरामदगी जिसमें राजकोष की किताबें और अन्य सामान थे, जो रात 9 बजे कार्यालय के लिए प्रस्थान करते समय पीड़ित द्वारा लिया गया था। तीन बटनों की बरामदगी, जो साबित हुए कि अभियुक्त की शर्ट के बटन थे, जो घटना का समय उसने पहने हुए थे। पत्थर की बरामदगी जिसका उपयोग अभियुक्त द्वारा पीड़ित के सिर को कुचलने के

लिए किया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घाव को घाव की तरह काटा हुआ पाया गया है जो कि मौत का कारण साबित होता है जैसा कि अभियुक्त ने बताया था। माता-पिता के घर से अभियुक्त द्वारा पहने गए कपड़ों की बरामदगी से संकेत मिलता है कि उसकी शर्ट में तीन बटन नहीं थे जो घटना स्थल पर पाए गए थे जो घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करते हैं। पीटीएस, मारोल के कार्यालय की चाबियाँ जिसे पीड़ित 7.12.1996 को अभियुक्त के साथ जाते समय अपने साथ ले गया था, अभियुक्त की निशानदेही पर पीटीएस मरोल के गार्डरूम से बरामद किया गया। जो चाबियाँ अभियुक्त के पास थीं, उनका अभियुक्त के पास से मिल जाना घटनाओं की शृंखला को स्पष्ट रूप से पूरा करता है। यह इंगित करने के लिए अभिलेख पर सबूत हैं कि अभियुक्त 8.12.1996 को पीटीएस, मरोल गया था और चाहता था कि पीटीएस मरोल का वेतन कार्यालय इस बहाने से खोला जाए कि वह पिछले दिन अपनी चाबियाँ छोड़ गया है। कार्यालय को खोलने की अनुमति नहीं दी गई और जिन गवाहों ने उन्हें 8.12.1996 की सुबह देखा था, वे अदालत के समक्ष गवाही दे चुके हैं। उच्च न्यायालय ने Exh. पी-24, मौके पर जो पंचनामा तैयार किया गया, पर विस्तृत रूप से विचार किया है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि पंचनामा एक समग्र दस्तावेज है, जिसमें अभियुक्त द्वारा बताए गए विवरण से संबंधित कुछ विवरण शामिल हैं, और इसमें ऐसे विवरण भी शामिल हैं जिन्हें घटना स्थल का पंचनामा कहा जा सकता है, और इसमें मृत शरीर का विवरण भी

शामिल है जिसे मृत्यु समीक्षा कहा जा सकता है। Exh. पी-24 को स्वतंत्र गवाह अरविंद वीरकर पीडब्लू-9 द्वारा देखा गया है जो घटना स्थल और शव और अन्य वस्तुओं की बरामदगी का स्वतंत्र गवाह था, जिसकी बचाव पक्ष द्वारा पूरी तरह से जिरह की गई थी। अभियुक्त का आचरण जो सबूतों के माध्यम से न्यायालय के सामने आया है, उसके द्वारा घटना के समय पहने गए कपड़ों की बरामदगी और घर से निकलते समय मृतक के पास मौजूद चाबियों की बरामदगी घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करते है और स्पष्ट रूप से इंगित करते है कि अभियुक्त ने ही अपराध किया था।

16. विद्वान न्याय मित्र द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि अभियोजन पक्ष किसी भी हेतु को साबित करने में विफल रहा। यह तर्क दिया गया है कि गार्डरूम से चाबियों के गुच्छे की बरामदगी सहित जो सबूत पेश किए गए थे, उनका उद्देश्य यह इंगित करना था कि वह कार्यालय में रखी नकदी की चोरी करना चाहता था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि कैसे वेतन कार्यालय में बहुत अधिक नकदी थी। अपराध करने का हेतु कुछ ऐसा होता है जो अभियुक्त के दिमाग में छिपा होता है और इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना एक असंभव कार्य है कि हत्यारे को किसी विशेष व्यक्ति को मारने के लिए वास्तव में क्या प्रेरित करता है। रविंदर कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य, 2001

(7) एससीसी 690 में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित निर्धारित किया हैः

> "18..... अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आम तौर पर एक असंभव कार्य है कि वास्तव में हत्यारों को किसी व्यक्ति विशेष की हत्या करने के लिए क्या प्रेरित करता होगा। कई मामलों में अभियोजन केवल संभावित मानसिक तत्व की ओर इशारा कर सकता है जो हत्या का कारण हो सकता है। इस संबंध में हम हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जीत सिंह {1999 (4) एससीसी 370} मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करना उपयोगी समझते हैं :
>
> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह याद रखने के लिए एक अच्छा सिद्धांत है कि प्रत्येक आपराधिक कृत्य एक हेतु के साथ किया गया था, लेकिन इसका परिणाम यह नहीं है कि कोई आपराधिक अपराध नहीं हुआ होगा यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के इसे करने के सटीक हेतु को साबित करने में विफल रहा है। जब अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सफल रहा कि अभियुक्त के मन में पीड़ित के प्रति कुछ गुस्सा था, परन्तु उस तरीके को अभिलेख पर लाने में असमर्थता कि

किस प्रकार अपराधी के मन में इस हद तक गुस्सा बढ़ गया होगा कि वह अपराध करने के लिए मजबूर हो गया, अभियोजन पक्ष की घातक कमजोरी के रूप में नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष के लिए उस व्यक्ति के प्रति अपराधी के मानसिक स्वभाव के पूर्ण आयाम को उजागर करना लगभग असंभव है, जिसे उसने नाराज किया है।"

17. आगे परमजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, 2010 (10) एससीसी 439 में, इस न्यायालय ने माना कि यदि हेतु साबित हो जाता है तो यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करेगा लेकिन इसकी अनुपस्थिति अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है। पैरा 54 में निम्नलिखित कहा गया था:

"जहां तक हेतु के विवाद्यक का सवाल है, मामला पूरी तरह से सुरेश चंद्र बाहरी (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय से कवर होता है। इसलिए, इस पर किसी और विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इससे भी अधिक, यदि हेतु साबित हो जाता है तो यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करेगा लेकिन इसकी अनुपस्थिति अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है। (देखिए: गुजरात राज्य बनाम अनिरूद्धसिंह [सुप्रा])"

18. उच्च न्यायालय ने हेतु पर विचार करते हुए पृष्ठ 46 पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

> "हालांकि अभियोजन हेतु के बारे में बहुत निश्चित नहीं है, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6 के सबूतों पर विचार करने पर, उस नकदी पर हाथ डालने के लिए जो उसके कब्जे में हो सकती थी, अभियुक्त के हेतु के बारे में एक हल्की संभावना बनती है, प्रारंभिक कहानी के विपरीत, अभियुक्त पीड़ित से इसलिए नाराज था, क्योंकि पीड़ित उसे बार गर्ल हेलेन फर्नांडिस से शादी की बात पर चिढ़ाता था। हेतु एक मानसिक स्थिति है, जो हमेशा अभियुक्त के मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से में बंद रहती है और यह आवश्यक नहीं है कि हेतु को स्थापित करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता अभियोजन की पूरी विफलता का कारण बने।"

हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए उपरोक्त दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उपरोक्त आधार में कोई तथ्य नहीं पाते हैं।

19. न्याय मित्र का कहना है कि पाटिल साहब से गवाह के रूप में परीक्षण नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अभियुक्त ने पीड़ित को बताया कि उसे पाटिल साहब ने कार्यालय में बुलाया है। जब साक्ष्य अभिलेख पर आ गए हैं, जिसमें पीडब्लू-1 प्रदीप मोहित, जो

7.12.1996 की रात को पीटीएस, मरोल में टेलीफोन ऑपरेटर थे, के साक्ष्य भी शामिल हैं कि पीड़ित के लिए कोई संदेश नहीं था, अभियोजन पक्ष द्वारा पाटिल काे पेश न करने का कोई महत्व नहीं है।

20. न्याय मित्र की अगला तर्क यह है कि पीडब्लू-8 कल्पना राउत ने अपने बयान में कहा है कि 7.12.1996 को पीड़िता रात 9:00 बजे खाना खाकर घर से निकली थी लेकिन पेट में कोई खाना नहीं पाया गया और मेडिकल रिपोर्ट मामले को झुठलाती है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तर्कों पर विचार किया है और पृष्ठ 33 पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

> "पीडब्लू-15 शांताराम द्वारा विधिवत समर्थित कल्पना का साक्ष्य इतना मजबूत है कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कल्पना को निश्चित रूप से पता था कि उसका पति पीडब्लू-15 शांताराम के भानजे के साथ चला गया है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने उस भतीजे को देखा था या नहीं और भी इस तथ्य के बावजूद कि क्या पीड़ित बिना रात्रिभोज के चला गया। इसलिए, पोस्टमार्टम नोट्स का वह भाग, जो पीड़ित के खाली पेट होने का संकेत देता है, कल्पना के बयान को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त प्रभावपूर्ण नहीं है, जो पीड़ित के अभियुक्त के साथ चले जाने की जानकारी का दावा करता है। इसलिए, हम यह मानने के

इच्छुक हैं कि कल्पना का साक्ष्य कि मृतक अभियुक्त के साथ चला गया था, स्वीकार्य है और अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय सबूतों के साथ इस परिस्थिति को स्थापित किया है।"

21. हम उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों का समर्थन करते हैं। वर्तमान मामलें में आखिरी बार एक साथ देखे जाने के अकेले साक्ष्य का मामला नहीं है, बल्कि घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करने और अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सभी साक्ष्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद अभियुक्त द्वारा दायर अपील को उचित रूप से खारिज किया है। हमें इस अपील में कोई आधार नहीं दिखता। अपील खारिज की जाती है।

निधि जैन अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रमेश कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायार्न्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।